भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3517
23.03.2026 को उत्तर देने के लिए

सीपीआई पद्धति का संसोधन

3517. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और संबंधित मुद्रास्फीति उपायों में सुधार के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सीधे मूल्य डेटा का उपयोग करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, जिसमें कवरेज का दायरा, शामिल किए गए शहर, डेटा संग्रह की समय-सीमा और उपभोग टोकरी (कंजम्पशन बास्केट) के भार में अपेक्षित परिवर्तन शामिल हैं;

(ग) क्या सरकार कृषि श्रमिकों के लिए मौजूदा सीपीआई (सीपीआई-एएल) और ग्रामीण श्रमिकों के लिए सीपीआई (सीपीआई-आरएल) के आधार वर्षों को समाप्त करने या संशोधित करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, जिसमें प्रस्तावित आधार वर्ष और कार्यप्रणाली शामिल हैं; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के मापन ढांचे को 2012=100 से 2024=100 तक व्यापक आधार संशोधन के माध्यम से सुदृढ़ किया है, जिसमें सीपीआई मद बास्केट और को अद्यतन करने के लिए नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) 2023-24 का उपयोग किया गया है। आधार संशोधन प्रक्रिया में प्रमुख सुधारों में कवरेज करने का विस्तार कार्यप्रणाली में परिष्करण, अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली को अपनाना और सीपीआई में प्रशासनिक एवं ई-कॉमर्स डेटा को शामिल करना है ताकि सीपीआई को अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक बनाया जा सके। पर्याप्त प्रतिनिधित्व और डेटा संग्रह की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, सीपीआई 2024 श्रृंखला में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के प्रतिदर्श बाजारों की संख्या 2295 से बढ़ाकर 2860 कर दी गई है। भारतीय घरों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग के कारण कीमतों के रुझानों का दर्ज महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए ई-कॉमर्स/ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वस्तुओं की लागत में होने वाले बदलावों को दर्ज करने

के लिए देश के 12 सबसे बड़े शहरों में 12 ऑनलाइन बाजारों को भी शामिल किया गया है, जिनकी आबादी 2011 की गणना के अनुसार 25 लाख से अधिक है।

(ख): वस्तुओं की लागत साप्ताहिक आधार पर ऑनलाइन/ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकत्र की जाती हैं। सीपीआई बास्केट की सभी वस्तुओं को संबंधित सबसे लोकप्रिय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मैप किया जाता है ताकि एमओएसपीआई के क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग(एफओडी) के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मूल्य संग्रह किया जा सके। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर लागत की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए, चारों सप्ताहों में निर्धारित दिनों और समय-सीमा पर कीमतें एकत्र की जाती हैं। सीपीआई संकलन में इन साप्ताहिक लेनदेन मूल्य अवलोकनों का उपयोग करके प्राप्त मासिक औसत मूल्य का उपयोग किया जाता है।

(ग) से (ङ): श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या (सीपीआई-एएल और आरएल) जारी की जाती है। आधार वर्ष 2019=100 वाली वर्तमान श्रृंखला जून 2025 में जारी की गई थी। इसमें सुदृढ़ और व्यापकता बढ़ाने के लिए कई कार्यप्रणालीगत सुधार शामिल किए गए हैं। इस श्रृंखला में 34 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें 787 प्रतिदर्शों गांवों से मूल्य एकत्र किए गए हैं और लगभग 150-200 वस्तुओं की एक सूची तैयार की गई है। यह अद्यतन उपभोग पैटर्न को दर्शाने वाले संशोधित अधिमान आरेखों का उपयोग करता है, मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए ज्यामितीय माध्य (जीएम) को अपनाता है और उद्देश्य के अनुसार व्यक्तिगत उपभोग के वर्गीकरण (सीओआईसीओपी)-2018 का अनुसरण करता है।

इसके अतिरिक्त, श्रम ब्यूरो के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 02.12.2024 को श्री ए.के. साधु (पूर्व महानिदेशक (एनएसएस), एमओएसपीआई) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है, ताकि सीपीआई-एएल/आरआई के आधार वर्ष के संशोधन की समीक्षा की जा सके और इसे हाल के वर्ष के अनुसार संशोधित किया जा सके।

****